झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

(लेटर पेटेंट अपीलीय क्षेत्राधिकार)

एल.पी.ए. संख्या 501/2023

1. झारखंड राज्य

2. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची, झारखंड पुलिस मुख्यालय, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला रांची

3. पुलिस महानिरीक्षक (बजट), झारखंड, झारखंड पुलिस मुख्यालय, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला रांची

4. पुलिस अधीक्षक, लातेहार, लातेहार कार्यालय, डाकघर एवं थाना- लातेहार, जिला लातेहार

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

विरुद्ध

1. शिव कुमार प्रसाद, पिता: मुंद्रिका प्रसाद, निवासी: ग्राम मोथा, डाकघर. भदारी, थाना-- अर्वल (टी.), जिला- अर्वल (बिहार)

.... प्रतिवादी

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची, कार्यालय: प्रोजेक्ट भवन, डाकघर धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला रांची

3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची, कार्यालय: प्रोजेक्ट भवन, डाकघर धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला रांची

4. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, रांची, कार्यालय: प्रोजेक्ट भवन, डाकघर धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला रांची

5. महालेखाकार, झारखंड, डोरंडा, रांची

6. प्रधान सचिव, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण, झारखंड राज्य, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, रांची

.... प्रारूप प्रतिवादी

न्यायाधीशगण: माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश,

माननीय न्यायमूर्ति नवीन कुमार

झारखंड राज्य के लिए : डॉ. (श्रीमती) वंदना सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता-III

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए : कोई उपस्थित नहीं

----

1 मार्च 2024

श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे. द्वारा:

I.A संख्या 2341/2024

यह अंतरिम आवेदन सीमांकन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें एल.पी.ए संख्या 501/2023 दाखिल करने में 256 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

2. इस आवेदन में अपीलकर्ता ने कहा है:

"4. कि यह कहा गया है और विनम्रता से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को इस माननीय न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4093/2014 में दिए गए आदेश के बारे में 17.05.2023 को पता चला।

5. इसके बाद, विभाग के संबंधित अनुभाग ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद 18.05.2023 को फाइल पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) के सामने पेश की। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिए गए आदेश के संबंध में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

6. इसके बाद फाइल को संबंधित अनुभाग में भेजा गया, और संबंधित अनुभाग ने 30.05.2023 को लातेहार पुलिस अधीक्षक को रिट याचिका में दिए गए आदेश के बारे में सूचित किया। इसके बाद, फाइल उच्च अधिकारी के सामने पेश की गई और 17.06.2023 को आदेश दिनांक 27.02.2023 के खिलाफ अपील दाखिल करने का निर्णय लिया गया।

7. इसके बाद रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त किए गए और 03.07.2023 को अपील के तथ्य एवं आधार की तैयारी के लिए अधिवक्ता को सौंप दिए गए। वही तैयार किया गया और 10.08.2023 को अपीलकर्ता विभाग को प्राप्त हुआ।

8. इसके बाद, पुलिस उप-अधीक्षक (कानूनी) ने इसे पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) के पास आवश्यक समीक्षा के लिए भेजा। इसे संबंधित अधिकारियों के पास सत्यापन के लिए भेजा गया और फिर पुलिस महानिदेशक के सामने पेश किया गया और 21.08.2023 को अनुमोदन प्राप्त हुआ।

9. इसके बाद अधिकारी को अपील को शपथ पत्र में रूपांतरित कर सभी रिकॉर्ड के साथ सरकारी अधिवक्ता को लेटर पेटेंट अपील दाखिल करने के लिए सौंपा गया।

10. इसके बाद, लेटर पेटेंट अपील को मसौदा तैयार किया गया, 09.09.2023 को शपथ पत्र में रूपांतरित किया गया और 12.09.2023 को दाखिल किया गया।

11. इसके बाद, इस माननीय न्यायालय के रजिस्ट्रार ने कुछ खामियों की ओर इशारा किया, और इसे अपीलकर्ता द्वारा ठीक किया गया।

12. इसके बावजूद, इस बीच अपील 256 दिनों से बाधित हो चुकी है।

13. अपीलकर्ता कहते हैं कि अपील दाखिल करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं थी बल्कि प्रक्रियात्मक देरी और अंतिम निर्णय लेने में अतिरिक्त समय लग गया।

14. अपील ज्ञापन दाखिल करने में हुई देरी जानबूझकर या जानबूझकर नहीं थी बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं, उचित दाखिले के लिए संवादों के कारण हुई है।"

3. आवेदन में किए गए दावों को देखते हुए, हमें लगता है कि अपीलकर्ता-झारखंड राज्य ने इस लेटर पेटेंट अपील को दाखिल करने में 256 दिनों की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया है और, तदनुसार, I.A संख्या 2341/2024 को मंजूरी दी जाती है।

<u>एल.पी.ए संख्या 501/2023</u>

4. झारखंड राज्य ने प्रतिवादी संख्या 1 (संक्षेप में "प्रतिवादी") को उनके विभिन्न अस्पतालों में उपचार के दौरान किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दिए गए रिट न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी है।

5. डॉ. (श्रीमती) वंदना सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता-III ने प्रस्तुत किया कि रिट न्यायालय द्वारा जारी निर्देश, सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 15 सितंबर 2006 के पत्र के माध्यम से सरकार के निर्देशों के तहत अनिवार्य आवश्यकता को नजरअंदाज करता है। माननीय राज्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि रिट न्यायालय नियोक्ता को

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लागू नियमों का पालन न करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

6. रिट न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि अपनी ड्यूटी के निर्वहन के दौरान उन्हें जीवन-धमकाने वाली चोटें आईं और रांची के रिम्स में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में, उन्होंने रांची के ऑर्किड अस्पताल में उपचार कराया, लेकिन जटिलताओं के कारण उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर और पटना के अस्पतालों में भेजा गया। चूंकि प्रतिवादी की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया और उसके बाद 15 अगस्त 2013 से 18 सितंबर 2013 तक नई दिल्ली के मैक्स हेल्थकेयर में एक इनडोर मरीज के रूप में उनका इलाज किया गया। माननीय राज्य अधिवक्ता ने यह इंगित करने का प्रयास किया कि प्रतिवादी को अपने रोजगार के दौरान कोई चोट नहीं आई थी, बल्कि उन्हें मस्तिष्क आघात हुआ था; दिनांक 30 अक्टूबर 2013 के आवेदन के माध्यम से। यह तर्क प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 4 में की गई दलीलों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में शामिल हो गए और उन्हें व्यापक जीवन-धमकाने वाली चोटें आईं। हमारे विचार में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन में उपरोक्त बयान और रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 4 में कोई विरोधाभास नहीं है। मस्तिष्क आघात के कारण किसी व्यक्ति द्वारा झेली गई चोट निश्चित रूप से जीवन-धमकाने वाली चोट होती है। इसके अलावा, प्रतिवादी को ड्यूटी के दौरान मस्तिष्क आघात हुआ और ऐसे घटना का घटित होना निश्चित रूप से दुर्घटना के रूप में कहा जा सकता है। "दुर्घटना" शब्द को उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए और इसके अलावा, यह वह भाषा है जिसे प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उपयोग किया गया है, जिस पर आधारित यह तर्क नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी ने रिट न्यायालय के समक्ष साफ हाथों से नहीं पहुंचा।

7. रिट न्यायालय के समक्ष तीन प्रतिवाद-पत्र दाखिल किए गए थे और उनमें से किसी में भी अपीलकर्ताओं ने रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में प्रतिवादी के उपचार को लेकर कोई संदेह नहीं उठाया। इसके विपरीत, लातेहार के पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 27 नवंबर 2013 में यह स्वीकार किया कि 23 अक्टूबर 2013 के मेमो के माध्यम से मानव अधिकार के पुलिस महानिरीक्षक ने प्रतिवादी के उपचार के लिए एक लाख रुपये मंजूर किए। यह भी विवादित नहीं है कि

प्रतिवादी द्वारा झेली गई चोट/रोग की प्रकृति ऐसी थी कि सरकार के निर्देश के तहत किसी अन्य अस्पताल में उपचार के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को प्रतिवादी पूरा कर सकते थे। आकस्मिक चोट *(Accidental Injury)* सरकार के निर्देशों के तहत 15 सितंबर 2006 के पत्र के माध्यम से दी गई घटनाओं में से एक है, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकार की जाती है। अंत में, माननीय राज्य अधिवक्ता ने *"राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार शर्मा" (2011) 4 एससीसी 257* में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि नियमों के तहत जो प्रदान नहीं किया गया है, उसे किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। हालांकि, जैसा कि *"महेश कुमार शर्मा"* के मामले में तथ्य बताते हैं, उस मामले में राज्य राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सीमा से परे चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया गया था। स्पष्ट रूप से, *"महेश कुमार शर्मा"* अपीलकर्ता-झारखंड राज्य को 27 फरवरी 2023 के रिट न्यायालय के आदेश, जो डब्ल्यू.पी (एस) संख्या 4093/2014 में पारित हुआ, को चुनौती देने में कोई सहायता नहीं देता।

8. रिट न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया है:

> 9. पक्षकारों की आपत्तियों को सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाना चाहिए। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से घायल था और उसने विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाया। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश लातेहार के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी, जहाँ वह संबंधित समय पर काम कर रहा था। ऐसे मामलों में, जहां किसी कर्मचारी की जान खतरे में हो, उत्तरदायी प्राधिकरणों को मामले को यांत्रिक रूप से नहीं देखना चाहिए और तकनीकी आधारों पर मामले को खारिज नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है। याचिकाकर्ता ने ड्यूटी के दौरान गंभीर चोटें खाई थीं, जो विवाद में नहीं है। राज्य प्राधिकरणों द्वारा किसी भी सिफारिश की अनुपस्थिति में, मामले को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।
>
> 10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शिवा कांत झा बनाम भारत संघ मामले में यह मुद्दा विचाराधीन आया था, जिसे JT 2018 (4) SC 269 में रिपोर्ट किया गया है, और उसके पैराग्राफ 13 और 14 इस प्रकार हैं:
>
> "13. ... ... "किसी भी चिकित्सा दावा को मान्य करने से पहले, प्राधिकरणों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि क्या दावेदार ने वास्तव में इलाज करवाया है और इलाज का तथ्य संबंधित डॉक्टरों/अस्पतालों द्वारा प्रमाणित अभिलेखों द्वारा समर्थित है।

एक बार यह स्थापित हो जाने पर, दावा को तकनीकी आधारों पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

14. ... ... संबंधित प्राधिकरणों को अधिक उत्तरदायी होने की आवश्यकता है और वे किसी कर्मचारी को उसके वैध प्रतिपूर्ति से यांत्रिक तरीके से वंचित नहीं कर सकते। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा देखभाल से वंचित न रहें। यह एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति में था, जो ऐसी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है कि योजना को लागू किया गया...।"

11. इस न्यायालय ने गोपाल चंद्र महतो बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य, W.P.(S) संख्या 5247/2018 और इसके अलावा सीताराम मेहता बनाम झारखंड राज्य और अन्य, W.P.(S) संख्या 3701/2016 के मामले में भी यही विचार दोहराया है।

12. वर्तमान मामले में, यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने ड्यूटी के दौरान गंभीर चोटें खाई थीं और इसके बाद याचिकाकर्ता का लातेहार, रांची, पटना, जमशेदपुर और दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इलाज हुआ था। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। केवल इस आधार पर कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश नहीं की गई थी या विशेष अस्पतालों में इलाज के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, याचिकाकर्ता के मामले को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता के मामले को यांत्रिक तरीके से खारिज करने से शाइलॉक और पोर्टिया की स्थिति की याद आती है। उत्तरदायी प्राधिकरणों ने शाइलॉक की तरह काम किया है। उन्होंने एक विशेष दस्तावेज़ पर जोर नहीं देना चाहिए था। जब मामला स्वीकार कर लिया गया है, तो इलाज को अस्वीकार नहीं किया गया है, तो यह उत्तरदायी प्राधिकरणों पर यह बाध्यता है कि वे उस कर्मचारी की दयनीय स्थिति पर विचार करें जिसने राज्य की सेवा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला है। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ड्यूटी पर था और उसने चोटें खाई थीं।

13. विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं, यहां पर, स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश देता हूँ कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर याचिकाकर्ता के इलाज पर खर्च की गई पूरी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए विचार करें। उत्तरदायी प्राधिकरणों को आदेश पारित करते समय जैसे पूर्व सिफारिश आदि जैसे दस्तावेज़ों पर जोर नहीं देना चाहिए। वे पूरी तरह से जानते हैं कि याचिकाकर्ता उनका अपना कर्मचारी था और मामले की सिफारिश

लातेहार के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी। इस प्रकार के मामलों में सहानुभूति दिखाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शिवा कांत झा (उपर्युक्त) मामले में किए गए अवलोकनों के मद्देनजर, उत्तरदायी प्राधिकरणों को आदेश की एक प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

14. उपरोक्त नियमों, दिशानिर्देशों, न्यायिक निर्णयों के संचयी प्रभाव के रूप में, पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा मेमो संख्या 58/अकाउंट सेक्शन दिनांक 04.02.2014 के माध्यम से जारी किए गए और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 21.12.2013 को जारी किए गए मेमो संख्या 786/बी के अनुवर्ती में और इसके बाद प्रतिवादी संख्या 5 को लिखे गए मेमो संख्या 799, दिनांक 15.10.2019 और इसके बाद याचिकाकर्ता से मेडिकल खर्चों के बिल और डिस्चार्ज स्लिप के दस्तावेज़ों की मांग करने वाले मेमो संख्या 665, दिनांक 16.10.2019 को रद्द और अलग किया जाता है। सभी भुगतान इसके बाद कानून के अनुसार छह सप्ताह की अवधि के भीतर किए जाएं।

15. इस प्रकार, यह रिट याचिका अनुमति दी जाती है।

9. जैसा कि हमने देखा, अपीलकर्ताओं ने किसी भी चरण में यह विवाद नहीं किया कि प्रतिवादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जो निश्चित रूप से आकस्मिक है, और प्रतिवादी द्वारा उठाया गया दावा उपरोक्त सरकारी पत्र के अंतर्गत पूरी तरह से आता है। हालांकि, झारखंड राज्य की ओर से यह कहा गया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से उन बिलों को प्रस्तुत करना होता है जिन्हें उपचार देने वाले अस्पतालों/संस्थानों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जो कि एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसे प्रतिवादी द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इस न्यायालय की समझ के अनुसार, ऐसी आवश्यकता का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की प्रामाणिकता की जांच करना है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां दावा की प्रामाणिकता खुद ही विवाद में नहीं है, केवल इस आधार पर कि प्रतिवादी ने उन चिकित्सा व्ययों/बिलों को प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जिन्हें उपचार देने वाले अस्पतालों/संस्थानों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को पूर्णतः अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता। रिट न्यायालय निश्चित रूप से नियोक्ता को अपने स्वयं के नियमों और विनियमों का पालन न करने का निर्देश नहीं

दे सकता, लेकिन नियोक्ता के ऊपर यह भी दायित्व होता है कि वह कार्यवाही में निष्पक्षता का प्रदर्शन करे। यह समस्या, जो कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा उत्पन्न की गई प्रतीत होती है और जो कि कई पत्राचारों और रिट न्यायालय के समक्ष दाखिल कई प्रतिवादियों में परिलक्षित होती है, को प्रतिवादी को एक प्रतिज्ञापत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साधारण निर्देश से हल किया जा सकता था, जिसमें उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा बिलों की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाती।

10. वर्तमान मामले में, रिट न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए विवादित निर्देश जारी किए हैं, जिनमें रिकॉर्ड पर लाए गए स्वीकार किए गए तथ्यों को ध्यान में रखा गया है, जो निश्चित रूप से प्रतिवादी के पक्ष में न्यायोचित विचार उत्पन्न करते हैं। यह वही प्रारंभिक समय था जब इंग्लैंड के चांसरी न्यायालय ने क़ानून के कठोर पालन के कारण मुकदमेबाज़ों द्वारा सामना की जाने वाली अजेय कठिनाइयों को पहचाना और यही वह समय था जब इक्विटी का जन्म हुआ। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यह न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए क़ानून और इक्विटी दोनों के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इक्विटी की अवधारणा, जो सामान्य क़ानून में क़ानून के कठोर अनुपालन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विकसित हुई, अब हमारे न्यायिक प्रणाली में गहराई से समाहित है और यही कारण है कि उचित मामलों में रिट न्यायालय आहत पक्ष को राहत प्रदान कर सकता है [संदर्भ: *“भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाम के.एस. जगन्नाथन एवं अन्य” (1986) 2 SCC 679*]।

11. जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है, रिट न्यायालय ने *"शिवा कांत झा बनाम भारत संघ" JT 2018 (4) SC 269, "सीताराम मेहता बनाम झारखंड राज्य और अन्य"* W.P(S) No.3701/2016 *और "गोपाल चंद्र महतो बनाम एम/एस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य"* W.P(S) No.5247/2018 में दिए गए विभिन्न निर्णयों का संदर्भ लिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि एक बार जब प्रतिवादी प्राधिकरणों ने रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली के अस्पतालों में प्रतिवादी द्वारा ली गई चिकित्सा उपचार को स्वीकार कर लिया है, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड

पर मौजूद सामग्रियों की जांच के बाद, हमने भी समान राय बनाई है और इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया है और तदनुसार, L.P.A. No.501/2023 खारिज की जाती है।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

(नवनीत कुमार, जे.)

सुधीर/एएफआर

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल (उच्च न्यायालय, रांची) अनुवादक द्वारा किया गया।**